HINDUSTAN TIMES, Online, 4.9.2021
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

TDP seeks NHRC intervention into arrests of protesting party workers

https://www.hindustantimes.com/india-news/tdp-seeks-nhrc-intervention-into-arrests-of-protesting-party-workers-101630696280118.html

Days after police action against some of the Telugu Desam Party (TDP) workers protesting against rising fuel prices, the party on Friday wrote to the National Human Rights Commission (NHRC), urging it to order a probe into alleged human rights violations of peaceful protesters in Andhra Pradesh.

In his letter, TDP Politburo member Varla Ramaiah asked the NHRC to take action against officials responsible for the "deterioration of law and order" in the state, ruled by chief minister Jagan Mohan Reddy's YSR Congress Party (YSRCP).

Ramaiah alleged that the state government and police violated people's fundamental right to speech and expression. "They were suppressing all voices of dissent and scuttling democracy at every step. If the erring officers were not made accountable to their suppressive actions, they would cause further erosion of democratic values in the state," read Ramaiah's letter.

On August 28, TDP workers staged a protest against the rising prices of petrol, diesel, and essential commodities, and raised slogans against the state government and CM Reddy. Police arrested several workers of the opposition party at various places.

"Several FIRs were registered against TDP leaders in Kotabommali, Dendulur, Pulivendula and Bommanahal police stations. More FIRs were registered in order to threaten people from expressing their dissent in a peaceful manner," Ramaiah said in the letter.

One of the TDP leaders to be arrested was former MLA from Denduluru seat Chintamaneni Prabhakar, who was reportedly taken into custody while he was attending a wedding.

Earlier, TDP national president and former chief minister N Chandrababu Naidu also wrote to the state's director general of police Gautam Sawang to release his party members. He claimed that the protests were held in a peaceful manner, by adhering to Covid-19 guidelines. He further claimed that the ruling party "unleashed" its police force to arrest TDP leaders, cadre and the general public.

The ruling YSRCP, however, dismissed the TDP's allegations, saying law was taking its due course on this issue. YSRCP spokesperson and Denduluru MLA Abbaya Chowdary Kothari said Chintamaneni Prabhakar had staged a protest with 150 people and disturbed a government review meeting.

The ruling YSRCP is numerically in a strong position after it won 151 out of the state's 175 assembly seats and 23 out of 25 Lok Sabha constituencies in the 2019 general and state elections.

Stating that Prabhakar has 74 cases registered against him for various offences, Kothari claimed the TDP leader has a history of attacking government officials, including police personnel.

WB चुनाव के बाद हिंसा: पूर्व न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर करेंगी कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा गठित SIT का नेतृत्व

https://sanjeevnitoday.com/national/violence-after-wb-elections-former-judge-manjula-chellur-to/cid4798540.htm

विगत अप्रैल-मई महीने में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में हुए आगजनी और हिंसा मामले की जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) का नेतृत्व करने का जिम्मा कलकत्ता हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर को दिया गया है।

ज्ञात हो कि 2 मई 2021 को जब पश्चिम बंगाल विधानसभा के परिणाम आए थे तो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल काँग्रेस (TMC) ने भारी बहुमत से चुनाव जीता था। चूंकि चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) और TMC के कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी तनावपूर्ण माहौल बन गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दलों के नेताओं के बीच भी काफी बहसा-बहसी हुई थी।

ज्ञात हो कि इस उग्र माहौल में जब चुनाव परिणाम TMC के पक्ष में आया तो तथाकथित रूप से TMC कार्यकर्ताओं ने BJP समर्थकों और कार्यकर्ताओं के ऊपर हिंसक हमले किए थे, उनके घरों को आग लगाने का प्रयास किया। यह भी आरोप लगाया गया था कि इस दौरान विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या भी की गई थी।

इस बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट में जब की याचिकाएं डाली गईं कि पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा की जांच सीबीआई से कराई जाए तो इन याचिकाओं के विरुद्ध भी कई याचिकाएं डाली गईं। अंततः कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद हिंसा की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की एक कमेटी बनाने का निर्णय सुनाया, जिसके बाद NHRC ने अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंप दी।

NHRC की रिपोर्ट और अन्य श्रोतों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विगत 19 अगस्त को कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था। सभी रेपोर्टों की जांच करने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपनी ओर से विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसके नेतृत्व का जिम्मा पूर्व न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर को दिया है।

बठिंडा में महिला, 3 वर्षीय बच्ची और पति HIV पाजिटिव आने का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

https://www.jagran.com/punjab/jalandhar-city-punjab-infected-blood-makes-mother-daughter-and-husband-hiv-positive-in-bathinda-21987255.html

ब्लड बैंक की लापरवाही से अस्पताल में दाखिल एक अनीमिया पीड़ित महिला महिला को संक्रमित खून चढ़ाने से एचआइवी पाजिटिव होने के मामले में नया मोड़ आया है। उसके एचआईवी पाजिटिव पाए जाने के करीब एक साल बाद अब उसकी तीन साल की बच्ची और पति भी एचआईवी पाजिटिव मिले हैं। समाजसेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष सोनू माहेश्वरी ने इसे लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी थी। आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने शिकायत पर केस नंबर 135752/सीआर/2021 दर्ज कर लिया है।

संस्था अध्यक्ष ने आयोग को भेजी शिकायत में बताया था कि बठिंडा के सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक ने मई, 2020 में अस्पताल में दाखिल एक अनीमिया पीड़ित महिला को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया था। महिला एचआईवी पाजिटिव हो गई थी। ब्लड बैंक और अस्पताल प्रबंधन/अधिकारियों ने महिला और उसके परिवार को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाने के बारे में कई महीनों बाद भी कोई जानकारी नहीं दी थी। इसके चलते महिला की तीन साल की मासूम बच्ची और उसका पति भी एचआईवी पाजिटिव हो गए। इसका खुलासा तब हुआ, जब सरकारी अस्पताल की टीम ने 27 अगस्त, 2021 को महिला और उसके परिवार के टेस्ट किए।

गरीब परिवार से है महिला

महिला गरीब परिवार से है। उसका पति मजदूरी करता है। परिवार को जब से इस घटना का पता चला है, उनका रो-रो कर बुरा हाल है। उनका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। सोनू माहेश्वरी ने कहा कि कई बेकसूर लोगों को जिंदगी भर के लिए इतनी बड़ी तकलीफ देने वाले ब्लड बैंक, सेहत विभाग के जिम्मेवार किसी भी आरोपित को बचने नहीं दिया जाएगा। उन्हें सजा दिलवाने के साथ-साथ पीड़ित परिवार को हर संभव मुआवजा दिलवाने के लिए भी संघर्ष किया जाएगा।

DAINIK JAGRAN, Online, 4.9.2021
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

मानवाधिकार आयोग पहुंचा एचआइवी पाजिटिव ब्लड चढ़ाने का मामला

https://www.jagran.com/punjab/bhatinda-case-of-transfusion-of-hiv-positive-blood-to-a-woman-21988578.html

सिविल अस्पताल बठिंडा के ब्लड बैंक की ओर से अस्पताल में दाखिल अनीमिया पीड़ित महिला को एचआइवी पाजिटिव ब्लड चढ़ाने के मामले में बठिंडा की समाजसेवी संस्था नौजवान वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष सोनू माहेश्वरी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी थी। इस पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।

संस्था अध्यक्ष ने बताया कि बठिंडा के सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक द्वारा मई 2020 में अस्पताल में दाखिल एक अनीमिया पीड़ित महिला को एचआइवी पाजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, जिससे महिला भी एचआइवी पाजिटिव हो गई, लेकिन ब्लड बैंक तथा अस्पताल प्रबंधन ने महिला तथा उसके परिवार को इस बारे में कई महीने बाद भी कोई जानकारी नहीं दी थी। इसके चलते महिला की तीन साल की बच्ची और पति भी एचआइवी पाजिटिव हो गए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब सरकारी अस्पताल की टीम द्वारा 27 अगस्त 2021 को महिला तथा उसके परिवार के टेस्ट किए गए। महिला गरीब परिवार से है, जिसका पति मजदूरी करता है। उन्होने आयोग से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपितों को सजा दिलवाने के साथ-साथ पीड़ित परिवार को हर संभव मुआवजा दिलवाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। मारपीट के दो मामलों में नौ लोगों पर केस दर्ज जिला पुलिस ने मारपीट के विभिन्न दो मामलों में छह ज्ञात और तीन अज्ञात समेत कुल नौ लोगों पर मामला दर्ज किया है।

थाना कैनाल कालोनी पुलिस को शिकायत देकर गुरजीत सिंह निवासी परसराम नगर बठिंडा ने बताया कि बीती 17 अगस्त को आरोपित मच्छी निवासी प्रताप नगर, ओमकार निवासी जोगी नगर व गोपी निवासी परसराम नगर बठिंडा ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया। मारपीट करने की वजह पुराना झगड़ा है। पुलिस ने तीनों आरोपितों पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

इसी तरह थाना नेहियांवाला पुलिस को शिकायत देकर गुरप्रताप सिंह निवासी गांव किल्ली निहाल सिंह वाला ने बताया कि बीती 19 अगस्त को आरोपित हरिदर सिंह निवासी गांव किल्ली निहाल सिंह वाला, हरप्रीत सिंह, गुरलाभ सिंह निवासी गांव बुर्ज महिमा और तीन अज्ञात लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया। मारपीट करने की वजह पुराना झगड़ा है। पुलिस ने सभी आरोपितों पर मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

NHRC probe sought into 'illegal' arrests: Varla Ramaiah

https://www.thehansindia.com/andhra-pradesh/nhrc-probe-sought-into-illegal-arrests-varla-ramaiah-704898

TDP politburo member Varla Ramaiah on Friday urged the chairperson of National Human Rights Commission (NHRC) to order a probe into human rights violations and illegal arrests of peaceful protesters in Andhra Pradesh and take stringent action against the officials responsible for the deterioration of law and order in the State. In a letter sent to the NHRC chairperson here, Ramaiah said that the AP government and the police force were resorting to gross violations of the fundamental rights and Article 19. They were suppressing all voices of dissent and scuttling democracy at every step. If the erring officers were not made accountable to their suppressive actions, they would cause further erosion of democratic values in the State. Also Read - Home Minister telling blatant lies on Disha law: Varla Ramaiah ADVERTISEMENT The TDP leader said that their party State leadership gave a call for State-wide protests on August 28 against the steep increase in petrol and diesel prices in AP. The protests were held in a peaceful manner and duly following the Covid safeguards. However, the ruling party has unleashed police force and accordingly TDP leaders, cadre and general public were arrested, while others were placed under house arrest. Several FIRs were registered against the TDP leaders in the Kotabommali, Dendulur, Pulivendula and Bommanahal police stations. Also Read - NHRC expresses displeasure on Telangana, AP over students' suicide ADVERTISEMENT Decrying the government's oppressive tactics, he said that at many places not only FIRs were registered under different sections, but some of the leaders were arrested and detained illegally and released later. The TDP leader further said, "Police are grossly neglecting and turning a blind eye to the mass gatherings, processions and meetings organised by the ruling YSRCP leaders." He expressed concern over the deteriorating law and order situation and growing excesses of the ruling YSRCP and the police force. He appealed to the National Human Rights Commission (NHRC) to conduct an inquiry and take appropriate action against the people responsible for such callous registering of cases.

TDP writes letter to NHRC on 'illegal' arrests of its leaders

https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/tdp-writes-letter-to-nhrc-on-illegal-arrests-of-its-leaders/article36267358.ece

The Telugu Desam Party (TDP) wrote a letter to National Human Rights Commission (NHRC) Chairman, urging him to conduct an inquiry into the allegedly illegal arrests, unlawful detentions and house arrests in the State. The TDP sought appropriate action against those responsible for registering these cases, which it claimed were callous.

In the letter dated September 3, TDP politburo member Varla Ramaiah said the party had organised State-wide protests on August 28 against the steep increase in petrol and diesel prices in Andhra Pradesh. The protests were held in a peaceful manner following COVID-19 protocol, to exert pressure on the State government to reduce fuel price, the letter said.

"In this backdrop, the ruling party has unleashed the police force and accordingly, TDP leaders, cadre and the general public were arrested, and others were placed under house arrest," he alleged in the letter.

The police, in violation of democratic norms and constitutionally-guranteed rights, illegally detained demonstrators, placed them under house-arrest, filed cases and made arrests, he said.

"The same police are turning a blind eye to the mass gatherings, processions and meetings organised by the ruling YSRCP leaders," he alleged, adding, "the YSRCP-led government has been using the pandemic as an excuse to target and victimise TDP leaders, cadre and sympathisers."

A quick and prompt action by the NHRC would help in restoring democracy, and upholding fundamental rights in general and freedom of expression guaranteed under Article 19 in particular, in the State of Andhra Pradesh, he said.

लाठीचार्ज मामला : NHRC ने दिया करनाल के डीसी और एसपी को नोटिस, 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी

http://zeenews.india.com/hindi/zeephh/agriculture/lathi-charge-case-nhrc-gave-notice-to-dc-and-sp-of-karnal-sought-report-in-4-weeks-vchr/978335

बसताड़ा में 28 अगस्त को किसानों पर हुए लाठीचार्ज मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने करनाल के डीसी और एसपी को नोटिस जारी किया है. आयोग ने 4 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार अयोग से मुलाकात की थी. कांग्रेस नेताओं ने पेन ड्राइव में लाठीचार्ज के वीडियो और मीडिया कवरेज की रिपोर्ट आयोग को सौंपी थी.

इस मामले में किसानों का सिर फोड़ने का आदेश देने का वीडियो वायरल होने के बाद करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा का तबादला कर दिया गया था. हालांकि किसानों की नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई है.

एसडीएम पर चले हत्या का केस

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि करनाल में सिर फोड़ने का आदेश देने वाले एसडीएम का तबादला एक नियमित स्थानांतरण है. यह प्रोत्साहन के साथ-साथ पदोन्नति भी है, सजा नहीं. हरियाणा सरकार हत्यारे अधिकारी को बचाने को नाकाम कोशिश कर रही है.

संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है 6 सितंबर तक हत्या का मुकदमा दर्ज कर अगर आयुष सिन्हा को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो करनाल में किसान 7 सितंबर से लघु सचिवालय का घेराव करेंगे. बता दें कि लाठीचार्ज के बाद एक किसान की मौत हो गई थी.

देश के कई हिस्सों में नाराजगी

इस बीच बंगाल, असम, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश आदि प्रदेशों के विभिन्न जिलों में आयुष सिन्हा को बर्खास्त कर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई.

ZEE NEWS, Online, 4.9.2021
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

संयुक्त किसान मोर्चा का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए धान खरीदी के नए नियम किसान विरोधी हैं.नियम समर्थन मूल्य पर कम से कम खरीद के लिए बनाए गए हैं, किसान संगठन नए नियमों को स्वीकार नहीं करेंगे.

PIONEER, Lucknow, 4.9.2021
Page No. 7, Size:(13.71)cms X (13.71)cms.

WB post-poll violence: 2nd CBI chargesheet in 2 days

SAUGAR SENGUPTA ■ KOLKATA

Acting fast after taking charge the CBI, investigating the graver offences post Assembly elections on Friday submitted a second chargesheet, this time in a North 24 Parganas murder case where a BJP supporter JP Yadav was bombed to death on June 6 by alleged Trinamool Congress miscreants.

This is the second chargesheet filed in two consecutive days with the first one being filed by the Central Agency in a Rampurhat murder case in Birbhum district.

"Four persons have been named in the chargesheet," a CBI source said adding more investigations were being conducted against other persons who had been named by the complainants.

The CBI is acting upon the orders of the Calcutta High Court which earlier directed a two-pronged probe deputing the central agency to investigate the graver offences whereas asking a Special Investigating Team of the State police to inquire into other offences.

In a related development former Calcutta High Court Chief Justice Manjula Chellur had agreed to supervise the SIT investigation into the "other" post poll "offences." According to sources unavailability of a retired Supreme Court Judge, for supervising the SIT probe — as was directed by the High Court — Justice Chellur was appointed for the task.

More than a hundred cases of murder, loot, rape and arson was reported post Assembly elections that saw Chief Minister Mamata Banerjee and Trinamool Congress roaring back to power for the third time in a row.

In the post poll violence an allegation of which was summarily rejected by the Chief Minister hundreds of BJP, Left, Congress and Trinamool Congress workers were attacked and their properties looted leading the Opposition BJP and the Left to raise demands for impartial probe accusing the State police of active connivance with the ruling party assailants.

Meanwhile, the TMC leadership which had already filed a petition in the Supreme Court against the High Court order continued to react strongly wondering why only the SIT and not the CBI was being monitored by the judiciary.

"Everyone knows how all the institutions have been saffronised by the BJP— from CBI to EC to NHRC and others —in that case where is the guarantee that the CBI will not conduct biased investigation … CBI's bias is a well-known fact so why only the SIT and not the CBI will be monitored by the Court," Sukhendu Shekhar Roy TMC Rajya Sabha MP said.

TELEGRAPH, Kolkata, 4.9.2021
Page No. 6, Size:(9.93)cms X (26.26)cms.

CBI makes third arrest in violence cases

KINSUK BASU

Calcutta: The CBI has made the third arrest in connection with the alleged political violence following the publication of Assembly election results in Bengal.

Ratan Halder was arrested from Shyamnagar adjoining Jagaddal in North 24-Parganas on Thursday night for allegedly murdering Sovarani Mondal, whose son was known to be a BJP worker.

Senior CBI officers said Sovarani had allegedly been hit with bamboo sticks on the head when she had come to the rescue of her son from assaulters who had attacked her family at Shyamnagar.

A team of CBI officers had reached the district a few days ago for the probe into Sovarani's murder.

The central investigating agency has been probing into alleged rapes and murders during the post-results violence as ordered by Calcutta High Court on August 19.

Four teams comprising a total of 21 officers and led by four joint directors has been touring parts of the state since the verdict.

On August 28, the CBI had arrested Bijoy Ghosh and Asima Ghosh from Nadia for their alleged involvement in the murder of BJP worker Ayan Mondal.

The CBI on Friday filed a chargesheet against four persons at Barrackpore court in connection with the alleged murder of Jayprakash Yadav, a BJP worker of Bhatpara in North 24-Parganas, on June 6. Yadav was killed following a spate of indiscriminate bombing at Bhatpara.

The four have been charged with murder under Section 302 of the Indian Penal Code.

The CBI had filed another chargesheet in Birbhum on Thursday in connection with the alleged murder of Manoj Jaiswal of Nalhati.

The agency has drawn up 34 cases involving heinous crimes like murder and rape in the aftermath of the poll results in Bengal.

SIT chairperson

Calcutta High Court on Friday appointed Justice (retired) Manjula Chellur as the chairperson of the Special Investigating Team (SIT) that was formed to probe alleged incidents of post-results violence, except murder and rape.

A high court bench headed by Acting Chief Justice Rajesh Bindal had on August 19 directed the state government to form the SIT that comprises police officers.

Justice Chellur had served as the Chief Justice of Calcutta High Court.

Justice Manjula Chellur.
File picture

NEW INDIAN EXPRESS, Hyderabad, 4.9.2021
Page No. 3, Size:(23.11)cms X (7.12)cms.

'Encounter' case: R&B staffer says accused hurled mud at cops

Panch witness had not mentioned this to the police, Judicial Magistrate or NHRC earlier

EXPRESS NEWS SERVICE @Hyderabad

THE accused in the rape and murder of a veterinarian at Shadnagar, had hurled soil in the eyes of the police party at the place of the 'encounter', panch witness in the case Rajashekar, Assistant Executive Engineer of R&B department, said. He had not mentioned the same in his statements before the police, Judicial Magistrate or even the National Human Rights Commission (NHRC) which had inquired into the 'encounter'.

The counsel for the commission appointed by the Supreme Court to probe the 'encounter', questioned him as to why he had not stated the same in his statements recorded immediately after the incident. When asked why he did so in the affidavit filed 11 months after the incident, he said while filing the affidavit, his advocate asked him to remember everything. "So I recollected everything and made my statement in the affidavit," he said during his cross examination on Friday.

He further stated that one of the accused took soil in his hands and hurled it into the eyes of the police party, after which the other three accused also threw soil at the police. Asked whether he had mentioned this in his statement to the NHRC, he said it was true that he had not. When asked

> **My advocate asked me to remember everything, so I recollected everything and made my statement in the affidavit**
> Rajashekar, Assistant Executive Engineer, R&B

why it was not mentioned in his previous statements that ACP Shadnagar gave directions to open fire in the air and commence counter-firing at the place of the 'encounter', he stated, "I made these statements before the police, but I don't know why it is not mentioned in my statement. I forgot to mention this before the magistrate. I made this statement to the NHRC, but it was not recorded."

Police fired in air to divert attention of accused: Witness

EXPRESS NEWS SERVICE @Hyderabad

THE police party which escorted the accused in the rape and murder case of a veterinarian at Shadnagar in 2019, had fired at least ten times in the air and then started counter firing to divert attention of the accused, panch witness Rajashekar, told the counsel for the Commission.

He also stated that he "had little bit of fear" when he was asked to "check the status of the accused after the firing incident" and that he had lied down on the ground at the time of firing.

He also stated that he saw one of the accused snatching a weapon from a Circle Inspector (CI) but he does know who snatched it from the Sub-Inspector (SI).

Both the officials were in the police party, who accompanied the accused to the place of the incident for recovering the articles belonging to the veterinarian, which were hidden by the accused after killing and burning her body.

However, when the counsel reminded him that he had stated the name of one of the accused in his statement before the magistrate, he said it was correct. When asked who told him the name of the accused who had snatched the weapon from the SI, he said that nobody told him, but he saw a weapon in his hand and said accordingly.

When asked how he knew the weapon belonged to the SI, he said that he had seen the weapon being snatched from the SI, but at the time of the incident, he did not know who had snatched the weapon. He added that the Circle Inspector's weapon was snatched first.

When the counsel for the Commission asked Rajashekar, "You stated before NHRC when the first accused was running, he was not carrying a weapon, stone, stick in his hands", he replied that the statement is not correct and added that the accused had a weapon in his hands.

'Didn't know if police tried to capture the accused'

Panch witness Rajashekar told the counsel for the Commission that he did not know if any of the police personnel tried to capture the accused and also if any of them had chased the accused

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 4.9.2021
Page No. 21, Size:(3.80)cms X (5.45)cms.

NHRC Chairman inaugurates 15 day online internship programme

Justice AK Mishra, Chairperson, NHRC said that good democracy cannot survive without respecting and protecting human rights. He was inaugurating the Commission's flagship 15 days online short-term internship programme. He said that the concept of human rights does not lay so much in legalese as much as it is embedded in our social behaviour and practices, having a spiritual tenor and tone. He said that India has a long tradition of respect for whole universe, including all living beings as in ecology and not just human beings.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 4.9.2021
Page No. 12, Size:(10.99)cms X (8.65)cms.

CBI files 2nd charge sheet in Bengal post-poll violence case, arrests one

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

KOLKATA: The Central Bureau of Investigation (CBI) on Friday filed its second charge sheet in the ongoing probe into post-poll violence in West Bengal and accused four people of murdering a Bharatiya Janata Party worker at Bhatpara in North 24 Parganas district on June 6, said lawyers aware of the development. The charge sheet was filed in the Barrackpore court.

CBI also arrested a man in connection with the murder of a BJP worker's mother in Jagaddal area of North 24 Parganas district. The victim, Shovarani Mondal, 64, was hit on the head by a stick, allegedly by Trinamool Congress (TMC) workers who came looking for her son on May 3, a day after the assembly polls results were announced.

CALCUTTA HC SAID RETIRED JUSTICE MANJULA CHELLUR WILL SUPERVISE THE SIT PROBE

Meanwhile, the Calcutta high court on Friday said a parallel probe into offences other than murder and rape will be supervised by former chief justice of Calcutta and Bombay HCs, Justice (retired) Manjula Chellur.

On July 19, the court ordered a CBI probe into alleged murders and rapes and a parallel probe by a special investigation team (SIT) comprising IPS officers posted in Bengal.

CBI's second charge sheet came within 24 hours of the first one filed in Birbhum district.

Commenting on the ongoing probe, TMC Rajya Sabha member Sukhendu Sekhar Roy, said, "The Calcutta high court ordered the probe on the basis of a report given by the National Human Rights Commission. The report was politically biased. CBI is only meeting families of BJP workers. It is not probing the deaths of the 13 TMC workers in violence."

BJP state chief Dilip Ghosh countered Roy. "What was the state police doing all these months? Why were charge sheets not filed and arrests not made? The TMC leadership is rattled because the CBI is acting tough and fast," Ghosh said.

DAINIK TRIBUNE, Delhi, 4.9.2021
Page No. 4, Size:(19.50)cms X (18.82)cms.

बीते 9 माह से बंद है दिल्ली के रास्ते

टीकरी बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर मानवाधिकार आयोग पहुंचे व्यवसायी

झज्जर, 3 सितंबर (हप्र)

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 9 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान आंदोलनकारियों को हटवाने के लिए बहादुरगढ़ के व्यवसायियों ने अब मानवाधिकार का दरवाजा खटखटाया है। व्यवसायियों के हवाले से सामने आ रहा है कि अभी तक करीब 2300 करोड़ रुपये का नुकसान आंदोलन की वजह से हो चुका है। उद्यमियों का कहना है कि अब आर्थिक नुकसान बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, टीकरी बॉर्डर को खुलवाया जाना जरूरी है।

उद्यमी अगले सप्ताह इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करने जा रहे हैं। बहादुरगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र छिकारा ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दी है, आयोग को लिखे पत्र में उन्होंने टीकरी बॉर्डर को जल्द खुलवाने की मांग की है। छिकारा का कहना है कि बहादुरगढ़ में करीब 12 हजार छोटी-बड़ी फैक्ट्रियां हैं और इनमें करीब 8 लाख कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली से आवागमन बंद होने की वजह से न तो फैक्ट्रियां में कर्मचारी आ-जा रहे हैं और न ही फैक्ट्रियों में तैयार और कच्चे माल की ढुलाई हो पा रही है। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली-रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित टीकरी बॉर्डर के मेन रास्ते समेत कई रास्ते बंद कर रखे हैं। जिसकी वजह से फैक्ट्री के सामान की ढुलाई के लिए दूरदराज के कच्चे-पक्के रास्तों से होकर गुजरना पड़ रहा है। छिकारा ने बताया कि इससे पहले वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उनका कहना है कि वे किसान विरोधी नहीं हैं। किसानों ने एक तरफ का रास्ता टीकरी बॉर्डर का खुला छोड़ रखा है। जहां से आसानी से वाहन आ-जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है और इसी रास्ते को खुलवाने के लिए अब उन्होंने मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया है।

किसानों ने रोका दिल्ली-रोहतक मार्ग

झज्जर (हप्र) : टिकरी बॉर्डर पर बिजली न मिलने से नाराज किसान आंदोलनकारियों ने दिल्ली-रोहतक नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। रात के समय किसानों ने करीब 2 घंटे तक नेशनल हाईवे रोके रखा। दरअसल, किसान करीब 5 घंटे के बिजली कट से परेशान होकर बिजली कार्यालय पहुंचे थे। लेकिन वहां भी उन्हें भरोसा नहीं मिला। किसानों का कहना है कि अधिकारियों के फोन बंद थे और वहां कोई भी कर्मचारी उन्हें यह नहीं बता रहा था की बिजली कट किसी लाइन फाल्ट की वजह है या फिर जानबूझकर किसानों की बिजली काटी गई है। इससे नाराज आंदोलनकारी किसानों ने आंदोलन स्थल से कुछ दूरी पर जाखोदा और कसार मोड़ पर जाम लगा दिया। जाम लगने से दिल्ली-रोहतक नेशनल हाईवे पर गाड़ियों पर लंबी लाइनें लग गईं। करीब 2 घंटे बाद जब बिजली आई तो किसानों ने जाम को हटाया।

'महिलाएं भी लेंगी महापंचायत में हिस्सा'

भिवानी (हप्र): उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत में महिलाएं भी हिस्सा लेंगी। जनवादी महिला समिति की जिला उपप्रधान संतोष देशवाल ने कितलाना टोल पर चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन धरने को संबोधित करते हुए यह बात की। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन की शुरुआत से ही महिलाएं भी किसानों के साथ संघर्ष कर रही हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कितलाना टोल के धरने पर 253वें दिन सांगवान खाप से नर सिंह सांगवान डीपीई, फौगाट खाप से धर्मबीर समसपुर, श्योराण खाप से बिजेन्द्र बेरला, किसान सभा से रणधीर कुगड़, किसान नेता गंगाराम श्योराण, मास्टर राज सिंह जताई, रामफल देशवाल, महिला नेत्री सुशीला घनघस, राजबाला कितलाना व रतनी डोहकी ने संयुक्त रूप से अध्यक्षता की।

TRIBUNE, Delhi, 4.9.2021
Page No. 13, Size:(19.63)cms X (19.95)cms.

Calcutta HC ex-CJ to oversee Bengal election violence probe

TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, SEPTEMBER 3

Justice Manjula Chellur (retd), first woman Chief Justice of the Calcutta High Court, will "overview the working" of the Special Investigation Team (SIT) constituted by the court to probe the cases of post-poll violence in West Bengal that took place after the declaration of the assembly election results on May 2.

The original order of the HC pronounced on August 19 had stated that a retired judge of the Supreme Court would monitor the SIT probe. However, no retired SC judge could be immediately found for assigning the job. As a result, the work of monitoring the SIT probe was entrusted to Chellur.

In its order on Friday, the five-judge Bench of the High Court led by Acting Chief Justice Rajesh Bindal said Chellur was offered the job "on account of immediate non-availability of a retired Supreme Court Judge to take up the assignment". The court asked the state government to pay Chellur Rs 10 lakh for the work. In addition, arrangements would have to be made for her travel and stay befitting a Chief Justice. So far, 34 FIRs have been filed by the CBI against those allegedly involved in murder or other heinous atrocities on BJP workers.

THREE-MEMBER SIT HEADED BY SAHOO

- The SIT is headed by Suman Bala Sahoo and has Soumen Mitra and Ranveer Kumar as members
- All of them are IPS officers of West Bengal cadre
- Justice Manjula Chellur, first woman CJ of Calcutta HC, will oversee the SIT

STOP POLITICAL WITCH-HUNT: TMC

- TMC leader Sukhendu Sekhar Ray has accused the Central agencies of harassing BJP's political opponents
- Ray was referring to ED summoning Abhishek Banerjee on September 6 for probe into an illegal coal mining case

PIONEER, Delhi, 4.9.2021
Page No. 5, Size:(13.53)cms X (13.07)cms.

WB post-poll violence: 2nd CBI chargesheet in 2 days

SAUGAR SENGUPTA ■ KOLKATA

Acting fast after taking charge the CBI, investigating the graver offences post Assembly elections on Friday submitted a second chargesheet, this time in a North 24 Parganas murder case where a BJP supporter JP Yadav was bombed to death on June 6 by alleged Trinamool Congress miscreants.

This is the second chargesheet filed in two consecutive days with the first one being filed by the Central Agency in a Rampurhat murder case in Birbhum district.

"Four persons have been named in the chargesheet," a CBI source said adding more investigations were being conducted against other persons who had been named by the complainants.

The CBI is acting upon the orders of the Calcutta High Court which earlier directed a two-pronged probe deputing the central agency to investigate the graver offences whereas asking a Special Investigating Team of the State police to inquire into other offences.

In a related development former Calcutta High Court Chief Justice Manjula Chellur had agreed to supervise the SIT investigation into the "other" post poll "offences." According to sources unavailability of a retired Supreme Court Judge, for supervising the SIT probe — as was directed by the High Court — Justice Chellur was appointed for the task.

More than a hundred cases of murder, loot, rape and arson was reported post Assembly elections that saw Chief Minister Mamata Banerjee and Trinamool Congress roaring back to power for the third time in a row.

In the post poll violence an allegation of which was summarily rejected by the Chief Minister hundreds of BJP, Left, Congress and Trinamool Congress workers were attacked and their properties looted leading the Opposition BJP and the Left to raise demands for impartial probe accusing the State police of active connivance with the ruling party assailants.

Meanwhile, the TMC leadership which had already filed a petition in the Supreme Court against the High Court order continued to react strongly wondering why only the SIT and not the CBI was being monitored by the judiciary.

"Everyone knows how all the institutions have been saffronised by the BJP— from CBI to EC to NHRC and others —in that case where is the guarantee that the CBI will not conduct biased investigation … CBI's bias is a well-known fact so why only the SIT and not the CBI will be monitored by the Court," Sukhendu Shekhar Roy TMC Rajya Sabha MP said.

ASIAN AGE, Delhi, 4.9.2021
Page No. 4, Size:(5.29)cms X (15.00)cms.

SHORT TAKES

3rd arrest in WB's post-poll violence

Kolkata: The CBI arrested a person in West Bengal's North 24 Parganas district in connection with its probe into a case of post-poll violence in the state, an agency source said on Friday. Ratan Halder, an accused in the murder of a BJP worker's mother following the declaration of assembly election results on May 2, was apprehended from Jagaddal area, the source said. The Central agency had on August 28 arrested two more persons - Bijoy Ghosh and Asima Ghosh — in Nadia district for allegedly being involved in the murder of a saffron party worker after the announcement of the poll results. The CBI had on Thursday filed a chargesheet in another case of post-poll violence in Birbhum district — its first since being handed over the probe into "heinous crimes". The chargesheet, submitted before the court, contains names of two accused allegedly involved in the murder of a BJP worker. — *PTI*

PUNJAB KESARI, Delhi, 4.9.2021
Page No. 9, Size:(20.40)cms X (20.33)cms.

पश्चिम बंगाल हिंसा का सच सामने आ पाएगा?

राजेश माहेश्वरी

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद हुई हिंसा और बर्बरता पर प्रदेश सरकार की उदासीनता के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सच सामने आने की उम्मीद जगी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनावी हिंसा के जघन्य मामलों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपी है। वहीं हाईकोर्ट ने प्रदेश में चुनाव बाद हुए अन्य हिंसा व आगजनी के मामलों की जांच के लिये राज्य पुलिस को एसआईटी गठन का आदेश दिया है। इस जांच की अंतरिम रिपोर्ट छह सप्ताह के भीतर अदालत को सौंपने के आदेश दिये गये हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अब तक 11 अलग-अलग मामलों में केस दर्ज किया है। इनमें रेप, हत्या और हिंसा जैसी वारदात शामिल हैं।

बीते दो मई को विधानसभा चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद सत्ता के नशे में चूर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया। नतीजों के बाद बंगाल में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को निशाना बनाया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसमें जहां 17 लोगों की हत्या हुई। वहीं महिलाओं से दुराचार जैसे जघन्य अपराध होने के आरोप लगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा की एक सूची तैयार की है जिसमें हत्या, हिंसा, आगजनी और लूटपाट की 273 घटनाएं होने का दावा किया गया है। पार्टी का दावा है कि उसके नौ लोगों की हत्या हुई है और हजारों लोग आतंक के मारे घर छोड़ कर भाग गए हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य सरकार ने इन घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाने की बजाय, टालमटोल वाला रवैया अपनाया। जिसके चलते हिंसा थमने की बजाय बढ़ती चली गयी। मीडिया रिपोर्ट से जो खबरें सामने आयी उसने सारे देश की चिंता को बढ़ा दिया लेकिन प्रदेश सरकार इन सारी घटनाओं पर बड़ी बेशर्मी से पर्दा ही डालती रही। प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी को मामले की पड़ताल के लिये जांच कमेटी भेजने को कहा था। विडंबना यह रही कि जांच कमेटी पर भी हमले हुए।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई उस पर बीते जून में सिविल सोसायटी ग्रुप ने रिपोर्ट तैयार की थी। पांच सदस्यीय कमेटी ने इस रिपोर्ट को केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी को सौंपा था। इस रिपोर्ट की कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं। यह टीम ग्राउंड पर लोगों से भी मिली है। कमेटी ने पाया है कि राज्य सरकार नागरिकों के मूल अधिकार के संरक्षण में पूरे तरीके से फेल रही। चुनाव के बाद हुई हिंसा संगठित हिंसा (प्रीमेडिटेटेड हिंसा) थी। जो निर्दोष लोगों पर अटैक कर रहे थे वो क्रिमिनल, माफिया डॉन, पुलिस रिकॉर्ड में सब क्रिमिनल थे। एक खास पार्टी के लोगों पर टारगेट करके हमले किए गए। पुलिस ने बड़ी लापरवाही की, शिकायत करने वाले को न्याय ना देकर उल्टा उनके ऊपर ही केस दर्ज किए गए। शिकायत के बावजूद पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। कई लोग घर छोड़कर पलायन कर गए उनके घरों को जला दिया गया। एक खास पार्टी के लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड छीन लिए गए। उनसे कार्ड वापसी के लिए तोलाबाजी (प्रोटेक्शन मनी) भी लेने की धमकी दी गई। कई जगहों पर क्रूड बम और पिस्टल की अवैध फैक्ट्री भी मिलीं।

बीते साल नवंबर में बंगाल यात्रा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2014 के बाद से 100 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता मारे गए हैं। शाह की बातों पर पलटवार करते हुए तृणमूल के सौगात रे ने कहा है कि वे (भाजपा) एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि अगर कोई प्रेमी आत्महत्या कर लेता है तो उसे भी एक राजनीतिक मौत कहा जा रहा है। जमीनी स्तर पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हिंसक टर्फ पर नियमित घटना बन गई है, बंगाल में पिछले दो वर्षों में कम से कम चार हाई-प्रोफाइल राजनीतिक मौतें देखी गई हैं। बीते नवंबर में उत्तर 24 परगना जिले के टीटागढ़ पुलिस स्टेशन से कुछ मीटर की दूरी पर भाजपा पार्षद मनीष शुक्ला को गोलियों से भून दिया गया था। पिछले साल जुलाई में, उत्तर दिनाजपुर जिले में भाजपा विधायक देवेन्द्रनाथ रॉय का शव रहस्यमय परिस्थितियों में लटका मिला था। टीएमसी विधायक सत्यजीत बिस्वास की पिछले साल सरस्वती पूजा के दिन नदिया जिले में पॉइंट जीरो रेंज पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी तरह प्रभावशाली टीएमसी नेता निर्मल कुंडू की जून 2019 में उत्तर 24 परगना जिले के निम्टा में गोली मारकर हत्या कर दी गई।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार पश्चिम बंगाल में 2018 में सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं हुईं। भारत भर में दर्ज 54 राजनीतिक हत्याओं में से 12 अकेले राज्य में दर्ज की गईं। आंकड़ों से पता चलता है कि 1999 और 2016 के बीच 18 सालों में पश्चिम बंगाल में हर साल 20 राजनीतिक हत्याएं हुईं। बंगाल में सबसे ज्यादा राजनीतिक मौतें 2009 में हुईं। इसके बाद 2000, 2010 और 2011 में 38 राजनीतिक हत्याएं हुईं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार राजनीतिक हत्या या राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक स्थायी संरचना है। 1972 के सिद्धार्थ शंकर रे मंत्रालय के बाद से राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। वामपंथी राजनीतिक रूप से राजनीतिक हिंसा का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ममता शासन के दौरान यह स्थायी हो गया है। बंगाल में जीवन के हर क्षेत्र में हिंसा जनता को जुटाने और स्थानीय स्तर पर राजनीति को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसलिए अब हिंसा का इस्तेमाल सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने राजनीतिक छोर के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। यह निश्चित रूप से सच है कि हिंसा का इस्तेमाल सत्तारूढ़ दल द्वारा क्षेत्र के प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए किया गया है, जबकि पुलिस और प्रशासन खामोश रहता है।

बंगाल में हुई हिंसा और बर्बरता पर राज्य पुलिस का रवैया सरकार का पक्ष लेने वाला ही रहा। पुलिस ने निष्पक्ष जांच और रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय सत्ता पक्ष का साथ दिया। राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते कई बार राज्यपाल जगदीप धनखड़ को सख्त टिप्पणियां करनी पड़ीं। निस्संदेह आरोपों-प्रत्यारोपों के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, जिसमें भाजपा की हार की हताशा भी शामिल है लेकिन यदि किसी के साथ राजनीतिक दुराग्रह के चलते अन्याय हुआ है तो उसे न्याय दिलाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी है।

न्यायिक प्रक्रिया से हटकर इस पूरे प्रकरण में कई गंभीर प्रश्न भारतीय लोकतंत्र के समक्ष हैं। आखिर आजादी के सात दशक के बाद भी किसी दल की हार-जीत के बाद हिंसा क्यों होती है। हिंसा को कौन बढ़ावा देता है? सरकारें उस पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों करती हैं? इसमें राजनीतिक दलों की क्या भूमिका होती है। निस्संदेह हिंसा का मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों व परंपराओं को नकारना ही है। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा मामले की जांच सीबीआई से करवाने के आदेश से राज्य सरकार नाखुश होगी। दरअसल, सीबीआई पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगता रहा है।